शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (423-429) April - June 2019

महात्मा गाँधी के आर्थिक विचार एवं खादी ग्रामोद्योगों का रोजगार सष्जन में योगदान

डा0 प्रेम नारायण यादव * **डा0 रेखा यादव****

एसो0 प्रोफे0, अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय डिग्री कालेज, दुगनाकुरी बागेश्वर, उत्तराखण्ड
Email: rekhayadav092@gmail.com

सारांश

भारत जैसे विविध सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक वाले देश में श्रम की प्रचुरता मानव संसाधन के रूप में विद्यमान है तथा देश प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियों एवं ऋतुओं की भरमार है ऐसी स्थिति में स्वदेशी गाँधीवादी उपाय खादी ग्रामोद्योगों से रोजगार सृजन की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि गाँधी जी स्वंय मानते थे कि बिना श्रम का भोजन पाप है। अतः गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के अनुकूल भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए श्रम का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। खादी एक विचार है जिससे मधुमक्खी पालन, वस्त्र एवं हाथ से कार्य करने वाले सरल एवं ग्रामीण उद्योगों में जान फूँकी जा सकती है। भारत का प्राण गाँवों में बसता है। रसद भी गाँव से शहरों में पहुँचती है यदि गाँव में खादी की पैठ को राजनीतिक इच्छाषक्ति द्वारा जनभावनाओं को अमलीजामा पहनाकर प्रचार प्रसार करके डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के (काका के पुरा) के सपनों को वैश्वीकरण में भारत को स्थापित किया जा सकता है तथा षहरों में ग्रामीणों के पलायन को रोका जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से खादी ग्रामोद्योगों में रोजगार सृजन करने की सम्भावनाओं की तलाश करने की कोशिश की गयी है और साथ ही रोजगार सृजन में समस्याओं के निराकरण के उपाय सुझाये गये हैं।

मुख्य शब्द *पुरा डा0 ए0पी0जे0 कलाम के गाँवों में शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं लाना खादी हस्त कौशल से वो सारे उद्योग जिसमें मानव पूँजी श्रम के रूप में लगी होती है।*

परिचय

खादी तथा ग्रामोद्योगों का आशयः

सीमित अर्थ में 'खादी' का अर्थ है कपास पर रेशम या ऊन सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र 'ग्रामोद्योग' का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थाई पूँजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन) प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार से अधिक न हो। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त राजस्व ग्राम 20 हजार तक आबादी वाले कस्बे शामिल है।

विस्तृत अर्थ में खादी का संबंध गाँधी के विस्तृत विचार से है –जैसे स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलन, ग्रामोद्योग, नैतिकता, सादगी, ट्रस्टीशिप, "अन्तिम व्यक्ति", शिक्षा, निरोगकाया, आचरण, स्वदेशी स्वाभिमान और मानव मात्र कल्याण आदि के अर्थों में है। अतिप्राचीनकाल से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योग तथा लघु व कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था की धुरी, कला कौशल के उत्कृष्ट स्वरूप एवं इतिहास के स्वर्णिम अध्याय रहे है। ब्रिटिश शासनकाल की स्वार्थपूर्ण नीति के झंझावत में फंस कर भारतीय परम्परागत ग्रामोद्योग अपने दैदीप्यमान आभा को गंवाने को बाध्य हुए। भारतीय संस्कृति व परम्परा के भावुक्तापूर्ण मोह में इस मुहिम ने टिमटिमाते द्वीप को अल्प ही सही परन्तु बनाए रखा। प्राचीनकाल से ही भारतीय वस्त्र बुनने की कला विश्व–विख्यात रही है। सूती और रेशमी कपड़ों की भारत जन्म भूमि रही है। ढाका का मलमल व 'चापा का कोसा' आज तक प्रसिद्ध है। इस प्रकार वस्त्र–निर्माण सम्बन्धी भारतीय कला की कुशलता तथा दक्षता के अनेकानेक अद्‌भुत प्रमाण उपलब्ध हैं। हमारे वेदों से लेकर पुराणों एवं विवाह गीतों में मानव निर्मित वस्त्रों का निर्विवाद प्रमाण है कि भारतीय वस्त्र कला उस काल में भी अपने चरम पर थी।

अध्ययन की समस्या

खादी को भूलते हैं तो हम ग्रामीण उद्योगों को भी भूल जाते है,' जो कुछ वर्ष पहले तक हमारी रसोई से लेकर शयनकक्ष और स्नानागार तक अपनी पैठ रखते थे। कश्मीरी शॉल, हिमाचली टोपी, जयपुरी रजाई, राजस्थानी बंधेज, रामपुरी चाकू, अलीगढ़ के ताले, बरेली का बेंत का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, मऊ की तांत की साड़ी या भागलपुर की रेशमी साड़ी असल में ग्रामोद्योग या कुटीर उद्योग की ही देन थे। किसी समय गांव के गांव इनसे रोजगार पा रहे थे और किसानों के लिए ये संकटमोचक का काम करते थे। लेकिन यह कहते ही प्रश्न उठता है कि क्या वाकई खादी और ग्रामोद्योग से इतना रोजगार मिलता है? और अगर मिलता है तो खादी अभी तक मध्यवर्ग या अभिजात्य वर्ग की चहेती क्यों नहीं बन पाई है? गांवों में बनने वाले अचार–मुरब्बे हमारी थाली से गायब क्यों हो गये हैं? ऑकड़ों में 31 मार्च 2015 को खादी उद्योग में 10.25 लाख से अधिक लोगों को रोगार मिला हुआ था। उनमें 878857 कताई करने वाले थे और 146551 बुनकर थे। केवीआईसी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2014 तक लगभग 140. 29 लाख अवसर पैदा हुए जो तुलनात्मक रूप से 14 प्रतिशत अधिक है। लेकिन जब संगठित और स्थायी रोजगार की बात आयी तो खादी में रोजगार घटता गया।

वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग रोजगार के बेहतर साधन हो सकते हैं क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता नहीं होती है। खादी की कताई के लिए तो लकडी के चरखे और कपास के अलावा केवल मानव श्रम की ही आवश्यकता होती है। पावरलूम या कपड़ों की छोटी इकाई लगाने में यदि 10 लाख रूपये खर्च होते हैं तो खादी की इकाई महज 20000 रूपये में लगाई जा सकती है। ग्रामोद्योग में जो भी छोटे–मोटे लेकिन आवश्यक उत्पाद बनते हैं, उनके लिए कच्चा माल सस्ता होता है और आमतौर पर गांवों में ही मिल जाता है। लेकिन फसल बिगड़ने की स्थिति में किसानों के लिए आजीविका का सर्वश्रेष्ठ साधन माने जाने वाले इन उद्योगों

के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं जिनके कारण लोगों को इनसे मोहभंग हो रहा है। संक्षेप में कम आय, कच्चे माल की समस्या, पूंजी का संकट, बाजार की कमी, बड़ी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा, ब्राण्डों की कमी और सुस्त सरकारी नीति जैसे संकट को अगर दूर किया जाय तो खादी ग्रामोद्योग में रोजगार की प्रचुर सम्भावनाएं मौजूद हैं और ऐसा करने से उद्योग का कायाकल्प होने में अधिक समय नहीं लग सकता है।

खादी गतिविधियों को औपचारिक रूप तब दिया गया जब अखिल भारतीय चरखा संघ का सन् 1925 में गठन किया गया। इसकी स्थापना के बाद अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ गठित किया गया। सन् 1953 में इसे बदलकर अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बना दिया गया और आखिरकार संसद के एक अधिनियम के जरिये अप्रैल 1957 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अस्तित्व में आया।

स्वतंत्रता पूर्व के दिनों से खादी ने एक लंबा सफ़र तय किया है और आज खादी उत्पादन में सूती, रेशमी और ऊनी खादी शामिल है जिसका कुल मूल्य 628.98 करोड़ रूपये और बिक्री 867.01 करोड़ रूपये बैठती है। इसके जरिये 9.81 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर मिलते हैं।

शोध का उद्देश्य–

भारतीय खादी ग्रामोद्योगों में रोजगार सृजन की सम्भावनाओं का अध्ययन करना।

खादी ग्रामोद्योगों की शासकीय नीतियों का अध्ययन करते हुए सुझाव प्रस्तुत करना।

समंकों का संकलन–

प्रस्तुत शोध–पत्र में सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु द्वितीय समंको को सम्मिलित किया गया है। जिसमें विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, किताबों, वेबसाइटों की सहायता ली गयी है।

ग्रामीण रोजगार और स्वदेशी की प्रतीक खादी

गाँधी जी के अनुसार "यदि खादी देश के लाखों लोगों को उपयोगी रोजगार नहीं दे पायेगी तो मेरी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। खादी मेरे लिए भारत की मानवीय एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है। असल में गाँधी जी ने जब खादी की अवधारणा को एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने रखा तो उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि यह देष के अपने संसाधनों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल के उपयोग से तैयार की जा सकती है। इसी आधार पर इसे स्वदेशी तथा आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बना कर राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया गया। एक ओर खादी गांवों में लोगों को घर बैठे अर्थोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने लगी तो दूसरी ओर खादी तैयार करना और खादी के वस्त्र पहनना देशभक्ति की पहचान बन गयी। यानी 'एक पंथ दो काज'। खादी की तर्ज पर स्वदेशी की परिभाषा हो गईः "उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन एवं इस्तेमाल की दिशा में सतत प्रयास करना।"

इस समय खादी उद्योग तथा उसमें जुड़ी अन्य गतिविधियों में 10 लाख से अधिक ग्रामीण कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें बुनकर तथा अन्य कारीगर शामिल है। आयोग

की इकाइयों में 2013–14 के दौरान 811.08 करोड़ रूपये मूल्य का उत्पादन हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 2013–14 में इस क्षेत्र में 3.79 लाख लोगों को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों से खादी के वस्त्र पहनने की अपील की। इसके बाद खादी वस्त्रों की बिक्री में वृद्धि होने की खबर है। खादी उत्पादन की इकाइयों को बैंक भी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देते हैं जिसके लिए सरकार या खादी ग्रामोद्योग आयोग सब्सिडी प्रदान करता है। इस प्रकार खादी गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण विकास में भी उपयोगी भूमिका निभाती है।

विगत वित्तीय वर्ष में खादी उद्योगों की प्रगति इस प्रकार थीः–

तालिकाः खादी ग्रामोद्योग में रोजगार की स्थिति–

क्रमांक	ग्रामोद्योगों समूह	कुल रोजगार– (व्यक्ति संख्या)	संदर्भित सकल रोजगार में हिस्सा (प्रतिशत)
1.	खनिज आधारित	7213184	14.08
2.	वनाधारित	5696776	11.12
3.	कृषि आधारित	9257216	18.07
4.	रसायन आधारित	6291044	12.28
5.	इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित वस्त्र सम्बन्धी	8770576	17.12
6.	सेवा आधारित	6798221	13.27
7.		7202938	14.06
योग		51229955	100

स्त्रोत– सर्वेक्षण रिपोर्ट (2008 दि एसोसिशएन ऑफ विपेज इंडस्ट्रीज)

आने वाले वर्षो में कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर देश के हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को ओर अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत सारे उपाय सरकार की ओर से भी किये जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र के निर्यात में भारी वृद्धि होने की संभावना है। हस्तशिल्प विकास आयुक्त का कार्यालय इसमें प्रशिक्षण, डिजाइन, विकास तकनीकी–सुधार, व्यापार संवर्द्धन, प्रदर्शन और प्रचार तथा निर्यात जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनागत कार्यक्रम को लागू करता है। हस्तशिल्पियों को रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काशीदाकारी, जरी और जरदोजी वाले वस्त्रों और आभूषणों की बिक्री बढ़ाने के विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये है। काष्ठ कला की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए संयुक्त विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। हस्तशिल्पियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भारत में इनकी पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई जा रही है। हस्तशिल्पियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना शुरू की है। जिससे सुदूर गाँवों में बैठे हस्तशिल्पियों और कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार कर उसकी निर्यात क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मूल्य संवर्द्धन से कारीगारों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक शोषण रोकने में मदद मिलेगी। आधुनिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय मानक भी ज्यादा–से–ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इसीलिए हस्तशिल्प निर्यातको को चाहिए कि वह इसे ध्यान से रखते हुए अपनी विपणन रणनीति को

हस्तशिल्प वस्तुओं को बनाने में बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाकर गुणवत्ता मानदंण्डों को शामिल करें। ब्राजील, अर्जेन्टीना दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के नए–नए बाजारों में भी ये वस्तुएँ लेकर पहुँचने का प्रयास करें। एक ओर जहाँ सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है वहीं निर्यातकों को भी गुणवत्ता, समय पर माल की आपूर्ति और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हस्तशिल्प की वस्तुओं का विदेशी बाजारों के साथ–ही–साथ भारतीय जीवन में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इधर भारतीय उपभोक्ताओं का भी इन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। गाँवों में तो ये वस्तुएँ वहाँ के रहन–सहन और जीवन का अंग हैं, अब तो शहरों में भी इनकी माँग होने लगी है। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात हाथ से छपे, वस्त्र कशीदेवाली शालें, कटाई तथा दूसरी कशीदाकारी वस्तुओं का होता है। गहने–जेवर, धातु–शिल्प, कान्टशिल्प, चित्रकारी के सामान तथा कलाकारी की दूसरी वस्तुएँ के निर्यात का नंबर इसके बाद आता है। भारत में जहाँ आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के रूप में हस्तशिल्प से रोजगार तथा अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाना रहा है वहीं नौवी योजना में हस्तशिल्प के विकास पर बल दिया गया है।

खादी ग्रामोद्योगों में सहायक योजनाएं

- ☞ मनरेगा, दीनदायाल ग्रामीण कौशल योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैन्डप इंडिया, विपणन विकास सहायता (एमडीए), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कुटीर ग्रामोद्योग योजना, व्यवसाय कौशल विकास योजना, कुटीर ग्रामोद्योग योजना, आदि।

समस्याएँ एवं समाधान

उजड़ते गाँव संकट में खादी ग्रामोद्योग

पिछले कुछ दशकों में सभी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में शहरीकरण को ही विकास का पर्याय मान लिया गया है। इसका पूरा प्रभाव भारत के अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों और प्रशासन पर दिखाई पड़ता है। उद्योग–व्यापार से जुड़े लोगों की दृष्टि में यही स्वाभाविक गति है और गांवों को उजड़ने में ही सबका हित उन्हें दिखाई देता है।

खादी ग्रामोद्योग की मूल समस्या नीतिगत है भारत की विकास की प्राथमिकताओं में गाँव, कृषि, ग्रामोद्योग का क्या स्थान है? समाज में उत्पादन और खपत के कौन से रिश्तों में हमारा विश्वास है? उत्पादक, कमाऊ, टिकाऊ, स्थायी स्वरोजगार का हमारी अर्थ नीति और योजना प्रक्रिया में क्या स्थान है?

उपरोक्त प्रश्न सभ्यता ओर संस्कृति से जुड़े है और व्यावहारिक धरातल पर जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इन प्रश्नों को अव्यावहारिक, काल्पनिक और कोरा आदर्शवाद कह सकते है। लेकिन इनके दृष्टि से हटने पर तो भूल–भूलैया और दुष्चक्र से हटने का कोई ठोस उपाय नहीं बचता। यह जरूर है कि तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संक्रमण काल का ऐसा व्यावहारिक पैकेज बनाना होगा कि हमारा समाज कालचक्र का सामना सफलतापूर्वक कर सके।

सुझाव–

खादी–ग्रामोद्योग क्षेत्र इस दिशा में ठोस योगदान कर सकता है। पांच कदम उठाने आवश्यक है–ग्रामीण औद्योगीकरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम–यह घोषणा वाजपेयी सरकार में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने की थी। गांधी की 125 वीं जयंती में नरसम्हिा राव समिति और 2001 में के.सी. पंत समिति की रिपोर्ट और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय में रोजगार सृजन से जुड़ी कई स्कीम को साथ लेकर कनवरजेंस करते हुए एन.पी.आर.आई. में एक करोड़ नये उत्पादक स्थायी रोजगार पैदा करने का लक्ष्य हो सकता है। खादी ग्रामोद्योग आयोग को राज्य सरकार–खादी बोर्ड, जिला प्रषासन और बैंकों के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए।

शोध एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से ठोस कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ाना होगा ताकि बाजार की प्रतियोगिता में ग्रामोद्योग के उत्पाद समुचित मुकाबला कर सकें।

इस दृष्टि से महात्मा गांधी संस्थान को सदृढ़ करना होगा और इस कार्य में समुचित निवेश करना होगा। वर्तमान स्थिति को दयनीय कहा जा सकता है। संसद में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने बताया है कि 2012–13 में ग्रामोद्योगी अनुदान की राशि 1306.79 करोड़ में से अनुसंधान एवं विकास मद की राशि मात्र 0.70 करोड़ है, यानी 0.1 प्रतिशत से भी कम इसका अर्थ है कि ग्रामोद्योग को बाजार की प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनुदान राशि को तत्काल दो प्रतिशत करना होगा। आगे चलकर आवश्यकतानुसार पांच प्रतिशत तक ले जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों और कारीगरों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

कारीगरों के बीच हुनर–खोज, हुनर को मान्यता और सम्मान का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। साथ ही नये हुनर और दक्षताएं–कुशलताएं विकसित करने का व्यापक कार्यक्रम चलाना होगा। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देनी होगी।

खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में विपणन और संस्थागत आधारभूत ढांचा विद्यमान हैं, इसका समुन्नयन और आधुनिकीकरण करते हुए इसका समुचित उपयोग हो सकता है। विपणन और संगठन–प्रबंधन में संस्थाओं और उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समानधर्मी स्वदेशी नेटवर्क से समन्वय बेहतर सिद्ध होगा। यही काम देश के बाहर पड़ोसी देशों–सार्क आदि के साथ मिलकर भी संभव है।

व्यापक संभावनाओं को साकार करने के लिए शीघ्र ठोंस कदम उठाने होंगे। उपरोक्त सुझाव राजनीतिक इच्छा षक्ति के साथ अमल में लाया जाय तो भारत की विशाल जनशक्ति को बेरोजगारी की समस्या पूरी तरीके से दूर की जा सकती है। गांधी जी का मानना कि था अगर हमें स्वराज्य की रचना अहिंसा के पाये पर करनी

है तो गांवों को उनका उचित स्थान देना होगा।

सन्द्रर्भ ग्रंथ

1. सहाय, शिवस्वरूप,(2004): *'प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास',* नरेन्द्र प्रकाश जैन मोतीलाल बनारसीदास बंगाली रोड, दिल्ली, पृ०–**309**
2. रमात, जी0एस0(2004–05): *'रीजनल रूरल बैंक्स खादी ग्रामोद्योग'*, 22(2)पृ0– **122–23**
3. ऋग्वेद 1/25/75/166/23
4. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली
5. भारतीय योजना आयोग की रिपोर्ट (2015), नई दिल्ली
6. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1952): खण्ड–1
7. प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मन्त्रालय–नई दिल्ली ।
8. कौटिल्य, अर्थशास्त्र अध्याय–11, अधि–2
9. शर्मा, श्रीराम, ऋग्वेद भूमिका–तृतीय संस्करण
10. जातक(2), पृष्ठ–18, **350–376**
11. वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ0–**53**
12. शिक्षा समुच्चय, पृ0–**208**
13. नेहरू, पंडित, *डिस्कवरी ऑफ इण्डिया,* पृ0–**241**
14. भोला, रविकुमार (2008): *'रूलर बैंकिंग प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्टस खादी ग्रामोद्योग'* खण्ड (9), पृ0 **348–99**
15. भट्टाचार्य, एस0एन0(1999): *'रूरल बैक्स अण्डर इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट'*, खादी ग्रामोद्योग, पृ० **77–109**
16. एम0के0गाँधी–यंग इण्डिया, हरिजन, मेरे सत्य के प्रयोग, गाँधी विकास मॉडल
17. भारतः *भारत सरकार प्रशासन विभाग,* (2006), पृ0–**87**
18. कुरूक्षेत्र (जून–1999,जनवरी–2015): *'ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका',* प्रकाशन विभाग, नई–दिल्ली
19. जागृति (जनवरी,1999): *'खादी पर पुनर्विचार'*,
20. जागृति : पत्रिका, जून 1999/2001
21. भारतीय रिजर्व बैंक (2005): *अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति का प्रतिवेदन*
22. Dutt & Sundram (2002): *'India Economy'*, S.Chand & Co. Ltd. Edition, Delhi.
23. Neal, Walter, C. 2007 Developing Rural India Policies, Politics and Progress, New Delhi.
24. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट। मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (रेडियो कार्यक्रम)
25. मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी (रेडियो कार्यक्रम)
26. कुरूक्षेत्र (2015), 61(12) पृ० **6–17**